

न्यायालय राजस्व अपील याचिका, जोधपुर
पीठाधीन अधिकारी श्री नरमदास बरहठ, आर.ए.एस.

2018-00294Jodhpur225RTA2018-131 Manglaram Vs State of Rajasthan

अंगाराम पुत्र उम्मेदराम जालि पटेल, निवासी- ग्राम
झंवर, तहसील जूनी, जिला जोधपुर।

..... अपील

ब

ली

म

1. राजस्थान राज्य जसि तहसीलदार जूनी, जोधपुर

..... रूपा.

अपील अन्वित धारा 225 राजस्थान कायदाका
अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर
जूनी जिलाक 15 जुलाई 2017 राजस्व यकरण
संख्या 271/2017 अधिनियम बलाम सरकार इत्यादि



उपस्थित --

श्री धनपत चौधरी, अधिवक्ता-अपील

श्री दरशाम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रूपा.

लि प्ल स

दिनांक : 05 अक्टूबर 2021

अपीलपुस्त ले न्यायालय सहायक कलेक्टर, जूनी द्वारा पारित
आदेश संख्या 271/2017 दिनांक 15 जुलाई 2017 के खिलाफ राजस्थान
कायदाका अधिनियम की धारा 225 के तहत अदातत होना के समक्ष
यह अपील जिलाक 31 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

राजस्थान अधिनियम
जोधपुर

1	क्र. 1	श्रीधराम पि. खाराम	1358	0.15.16
क. गांव का	दर. खातेदार का नाम मय	पिता का नाम	पत्न्या	रकबा रकबा रकबा रकबा रकबा
स. नाम				दर. दर. दर. दर. दर.
श. क्र. 1				

आदेश पारित किया--

करते हुए वरगीम की जाकर तदनुसार अभिलेख संघारित किये जाने का किये जाने तथा राजस्व जांचों में भूल खसराज की शीम में से कम तदनुसार राजस्व रिफाई में रीरगुमनिकल रास्ते के रूप में अमल-दस्तावे रकबा रीर गुमनिकल रास्ते हेतु सहमति से छोड़ा गया रकबा मानते हुए निम्नलिखित आराखियात में से उनके खसरा नम्बर के आने अधिक 251ए में प्रदत्त शर्तियों का पालन करते हुए राजस्व नाम क्र. 1 में स्थित केम कोट गौरी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा गांव रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गौरी हठका क्र. 1 व अ-अभिलेख निरीक्षक क्र. 1, उपखण्ड अधिकारी क्र. 1 की क्रिया रि. राजपाल के रास्ते के उपयोग हेतु प्रमाणपत्र एवं पटवारी नारायणराम पि. खीयाराम वौरह, भंगाराम पि. उम्बेदराम, कमल वौरह, बंगाराम/पंगाराम, शराराम, सोहनराम पि. दुर्गाराम वौरह, पि. खाराम, भंगाराम पि. पूंगाराम वौरह, बंगाराम पि. उदराम प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रमाणपत्र शीयाराम



अपील वजह विचार दर. रजिस्टर की गयी।
 विगत को शमा किये जाने का निवेदन किया। जिसके आधार पर
 तब एक प्रमाणपत्र मय प्रमाणपत्र पेश कर अपील पर-दल करने में हुए
 अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के

M.

उक्त आदेश के खिलाफ अपीलानुस ल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आगौच्य अपील पेश की है। वरस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलानुस का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर और किए बिना ही अपीलार्थीन आदेश पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीन शवागाराम की कृषि भूमि खसरा नं. 1342 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा वाक मौजा झंवर तहसील गूणी जिला जोधपुर के संबंध में दिनांक 15.07.2017 को जेर भूमिकन रास्ते हेतु 06 बिस्वा 03 बिस्वाधी भूमि दर्ज किये जाने का आदेश अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित कर भारी भूल की है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पत्रावली पर में वर्णित तथ्यों के आधार पर खारिज किये जाने के योग्य है। अपीलार्थीन आदेश के अवलोकन से ज्ञात है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये वौर ही दिनांक 15.07.2017 को हुका पटवारी झंवर, भूमि-अधीनस्थ निरीक्षक झंवर तथा न्याय तहसीलदार गूणी



2	झंवर	शवागाराम प्ल. पूंगाराम वौरह	1354	0.11.06
3	झंवर	बागाराम प्ल. उदराम वौरह	1353	0.07.07
4	झंवर	बागाराम प्ल. उदराम वौरह	1349	0.07.09
5	झंवर	बेगाराम/पंगाराम	1345	0.07.11
6	झंवर	शराराम, सीताराम प्ल. 1344	1344	0.06.00
7	झंवर	नारायणराम प्ल. खीयाराम	1343	0.09.05
8	झंवर	शवागाराम प्ल. उम्हदराम	1342	0.06.03
9	झंवर	वमल कियार प्ल. रामपाल	1339	0.09.05

राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय
जोधपुर

लायक नहीं है।

परिधि में नहीं आने एवं विधिसम्मत: नहीं होने से यथावत रखे जाने
आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत धारा 251-ए की
उत्तरी उपस्थिति या सहमति रिपोर्ट पर नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय
न्यायालय, कर्मिकेशोर जिला की शीर्ष रिपोर्ट के रूप में दर्ज की गई है,
से रास्ता चाहिए। खातेदार श्रीयाराम, अणाराम, बगाराम, शेरराम
यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन खातेदारों को कौनसे खासना में
नाम के अलावा संपूर्ण परिवारियां शामिल होनी चाहिए हैं। यथाना पत्रों में
प्राधान्य पर पूर्ण रूप से भरोसा है। प्रस्तुत यथाना पत्रों में आवेदकों के
प्राधान्य से प्रकट नहीं होता है तथा न ही आवेदकों द्वारा प्रस्तुत
सूचिकाई का अवसर प्रदान किया जाना श्री अधीनस्थ न्यायालय की
अधीनस्थ आदेश पत्रों के पठने पर पक्षकार बनाया जाकर
है, उसमें विलंब खासना नबखान के रिपोर्ट्स सभी खातेदारों को
व उनके खातेदारों की जो विलंबका उक्त आदेश में अंकित की गयी
अधीनस्थ आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत विधिगत खासना नबखान
अधीनस्थ न्यायालय की प्राधान्य में उपलब्ध ही नहीं है। यही नहीं,
कोई सहमति पत्र अथवा रास्ता प्रदान करने वाले हैं। कोई प्राधान्य
का आम रास्ते हैं। उपरोक्त करने बाबत सहमति देने वाले संबंधित
अवलोकन करने पर पता जाता है कि अधीनस्थ खातेदारी की कृषि शीर्ष
व्यापारों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की प्राधान्य का



अन्य विधायकश्रीमान की जाती है।

में की गयी बहस पर विचार करके हुए न्यायालय में अधीनस्थ अधीनस्थ
अधीनस्थ में विलंब एवं अधिवक्ता-अधीनस्थ द्वारा इस संबंध
की ओर से प्रस्तुत प्राधान्यक अनुरोध धारा 5 भारतीय संसद सीमा

